नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 013
दि. 13.05.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मंत्रियों के काफिले से आधे वाहन हटेंगे, ईंधन की खपत कम करने को लेकर सीएम योगी ने लिया फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद से बचें।

(जीएनएस)।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को प्रदेश में व्यावहारिक रूप से अपनाए जाने की अपील की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50 प्रतिशत की कमी की जाए। काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री जी का सरकारी बैठकों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि के वर्चुअली आयोजन पर जोर रहा।

सीएम ने की अपील

मुख्यमंत्री ने वैश्विक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रदेशवासियों को जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में उथल-पुथल है, ऐसे में सभी को सावधानी बरतनी होगी। प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पालन करने के लिए राज्यों को तैयार रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे आयोजित किया जाए। इस अभियान से सरकारी कर्मचारियों, स्कूलों-कॉलेजों के विद्यार्थियों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को भी जोड़ें।

वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित

औद्योगिक विकास विभाग व आईआईडीसी द्वारा औद्योगिक संस्थानों, बड़े स्टार्टअप्स आदि में वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं जहां बड़ी संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुशंसा के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। शिक्षा विभाग के सेमिनारों, बैठकों, वर्कशॉप समेत सरकारी बैठकों आदि का आयोजन वर्चुअली माध्यम से किया जाए। राज्य सचिवालय/निदेशालय की 50 प्रतिशत आंतरिक बैठकें भी वर्चुअली की जाएं। स्कूल-कॉलेजों में स्कूली बस के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। आवश्यकता पड़ने पर परिवहन निगम की बसों को भी स्कूलों से जोड़ा जाए। पीक ऑवर में ईंधन का उपयोग कम करने के लिए कार्यालय समय को अलग-अलग बैचों में बांटा जा सकता है।

ईवी के प्रयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन, साइक्लिंग, कार पूलिंग, ईवी के प्रयोग

पर जोर दिया। कहा कि जिन शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है, वहां लोग इसका अधिकतम प्रयोग करें। अधिक मांग वाले मार्गों पर बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से विद्युत बचाने की भी अपील की। साथ ही कहा कि सरकारी भवनों, घरों, निजी प्रतिष्ठानों आदि में अनावश्यक बिजली का प्रयोग न हो। निजी प्रतिष्ठानों/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आदि में रात 10 बजे के बाद सजावटी लाइटों का न्यूनतम प्रयोग हो।

अगले छह माह तक गैर आवश्यक विदेशी यात्राएं न करें

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक साइकिलिंग शेयरिंग योजना को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगले छह माह तक गैर आवश्यक विदेशी यात्राएं न करें। सीएम ने नागरिकों, वेडिंग प्लानर्स आदि से देश में ही आयोजन करने की अपील की। कहा कि यूपी में भी हैरिटेज, ईको साइट्स, किले समेत अनेक अच्छे स्थल हैं, वहां भी डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा दें। विजिट माई स्टेट अभियान शुरू किया जाए, जिसमें वेलनेस, ईको, ग्रामीण, वन्यजीव तथा खानपान पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिले। यूपी पहला राज्य है, जिसने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीन' को लागू किया। सीएम ने संग्रहालयों, स्मारकों आदि को कुछ समय निःशुल्क किए जाने का निर्देश दिया।

स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए

पर्यटन विभाग होटल, एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट आदि के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दे। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां भी उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिक हैं, उन्हें प्रदेश में घूमने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए शॉपिंग फेस्टिवल, हेरिटेज टूर, गोशाला, टेंपल आदि का दर्शन कराएं। स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा दें।त्योहारों, शादियों समेत विभिन्न आयोजनों में भारत में बने उपहारों, उत्पादों, हस्तशिल्प सामग्रियों को बढ़ावा दें। राज्य सरकार की ओर ओडीओपी तथा जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को उपहार के रूप में दिया जाए। स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए।

आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी कदम

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य, घरेलू बचत व आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम जरूरी है। नाट्य श्रृंखलाओं के जरिए लोगों को जागरूक करें। स्वास्थ्य विभाग पोषण जागरूकता शिविर लगाए। इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। स्कूलों, कॉलेजों, जिला, निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, सरकारी कैंटीन, मिड डे मील, जेल, छात्रावास, पुलिस मेस आदि में भी खाद्य सामग्रियों में तेल के कम प्रयोग पर जोर दिया।

सीएम ने फॉर्मर रजिस्ट्री पर विशेष जोर दिया

स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होटल, हलवाई, रेस्तरां, ढाबा, स्ट्रीट फूड आदि के यूनियन के साथ संवाद स्थापित कर कम तेल वाले खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने पर जोर दें। सीएम ने कृषि विभाग को नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिया। प्रदेश की गोशालाओं में 14-15 लाख गोवंश हैं, इनके गोबर का भी उपयोग किया जाए। सीएम ने फॉर्मर रजिस्ट्री पर विशेष जोर दिया।

सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह

सीएम ने सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। कहा कि प्रशासन स्थानीय ज्वेलर्स एसोसिएशन, व्यापारियों आदि के साथ भी बैठक कर उनकी चिंताओं को दूर करे। प्रदेश में पीएनजी नेटवर्क का मिशन मोड पर विस्तार करें। इसके कनेक्शन को बढ़ाने पर जोर दें। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी बैठक करें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी प्रोत्साहित करें। इसके जरिए रूफटॉप सोलर को अपनाए जाने के लिए लोगों को प्रेरित करें।

आपरेशन सिंदूर पर बीजिंग बेनकाब! भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा- हमारी जानकारी 100% सच साबित हुई

(जीएनएस)।

मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध, जिसे भारत में 'ऑपरेशन सिंदूर' कहा जाता है, उसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि इस जंग के दौरान उसने जमीनी स्तर पर पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी।

चीन के सरकारी चैनल उउळश पर हुए इस खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को इस मिलीभगत की जानकारी पहले से थी और अब यह पूरी दुनिया के सामने सच साबित हो गई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय का करारा जवाब

चीन के इस कबूलनामे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी की है। प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि जो देश खुद को जिम्मेदार

मानते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि आतंकी बुनियादी ढांचे को बचाने में मदद करने से उनकी वैश्विक छवि पर क्या असर पड़ता है। भारत ने साफ किया कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों को दुनिया की नजरों में अपनी गिरती साख और प्रतिष्ठा पर विचार करने की जरूरत है।

चीन की स्वीकारोक्ति और SCMP की रिपोर्ट

दरअसल, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन के सरकारी प्रसारक ने एक इंटरव्यू में यह माना कि उनके विशेषज्ञ युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को तकनीकी मदद दे रहे थे। अब तक चीन खुद को इस मामले में निष्पक्ष बताता आया था, लेकिन इस नए बयान ने उसकी पोल खोल दी है। यह खुलासा साबित करता है कि चीन ने न केवल कूटनीतिक रूप से, बल्कि युद्ध के मैदान में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था।

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही संकेत दिए थे कि पाकिस्तान की तकनीकी क्षमताओं के पीछे बीजिंग का हाथ है।

पीएम मोदी की अपील पर सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला, काफिले में घटेंगी गाड़ियां

प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील के अनुरूप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

मोहन यादव अपने कार काफिले को आठ वाहनों तक सीमित रखेंगे और यात्रा के दौरान वाहन रैलियों पर रोक लगाएंगे। यह कदम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देता है और अधिकारियों द्वारा किफायती यात्रा के लिए पूरे राज्य में एक उदाहरण स्थापित करता है।

उपराष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान -एम्स नई दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

उपराष्ट्रपति ने कहा एम्स सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि अब उन्हें स्थापित कर रहा है

उपराष्ट्रपति ने कहा कोई भी कृत्रिम बुद्धिमता तकनीक मरीज के बिस्तर के समीप डॉक्टर की मौजूदगी का विकल्प नहीं हो सकती

उपराष्ट्रपति ने वहन करने योग्य शुल्क के साथ उत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए एम्स की सराहना की

उपराष्ट्रपति ने एम्स से उत्तीर्ण डॉक्टरों से सहानुभूति और सत्यनिष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का आह्वान किया

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान - एम्स, नई दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एम्स के योगदान का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्थान चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जो रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित करते हुए आम लोगों के लिए काफी सस्ते दर पर इलाज प्रदान करने वाला बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने की क्षमता से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तक, "एम्स ब्रांड" समूचे भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भरोसे और सत्यनिष्ठा का पर्याय बन गया है।

उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक मानकों से समझौता किए बिना बड़ी संख्या में रोगियों के कुशल चिकित्सा प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और एम्स के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, संस्थान के निदेशक और संकाय सदस्यों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि एम्स दशकों से ऐसे विशेषज्ञ तैयार करता आ रहा है जिनमें चिकित्सा उत्कृष्टता के साथ ही नैतिकता और सहानुभूति की भावना प्रबल है। इसी भावना के साथ संस्थान के पूर्व छात्र विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में अग्रणी पदों पर आसीन हैं।

इस वर्ष के आरंभ में अंटार्कटिका में दूरस्थ रोबोटिक अल्ट्रासाउंड आयोजित करने में एम्स की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसने सिद्ध कर दिया है कि भौगोलिक स्थिति अब भारतीय चिकित्सा उत्कृष्टता में बाधक नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग के लिए भारत-फ्रांस केंद्र सहित संस्थान के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोगों का भी उल्लेख किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स अब स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का उल्लेख करते हुए श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि एम्स ने केवल दो वर्षों में 40 पायदान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 105वां स्थान हासिल कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि संस्थान शीघ्र ही इस रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हो जाएगा और एक दिन दुनिया का अग्रणी संस्थान बनेगा। उन्होंने कहा कि एम्स ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत मेडिकल कॉलेजों को दी जाने वाली वार्षिक श्रेणी में 2018 से 2025 तक लगातार शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

उपराष्ट्रपति ने संस्थान के संकाय सदस्यों और अनुसंधानकताओं की सराहना करते हुए कहा कि एम्स की उत्कृष्टता वर्षों से इसके संकाय सदस्यों को मिले असंख्य पद्म पुरस्कारों में परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि इस विशिष्ट सूची में 2 पद्म विभूषण, 15 पद्म भूषण और 51 पद्म श्री पुरस्कार विजेता शामिल हैं, जबकि 57 संकाय सदस्य विश्व स्तर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में एम्स संस्थानों के विस्तार का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा काफी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए देशभर में और अधिक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों की भी सराहना की।

उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे इस पेशे में भारतीय स्वास्थ्य सेवा के एक निर्णायक मोड़ पर प्रवेश कर रहे हैं, जब एक राष्ट्र, एक स्वास्थ्य की परिकल्पना अधिक एकीकृत, न्यायसंगत और भविष्योन्मुखी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को आकार दे रही है।

नीट यूजी 2026 पेपर लीक से देशभर में भारी बवाल! एनटीए ने रद्द की परीक्षा, दिल्ली में सड़कों पर उतरे छात्र

(जीएनएस)।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ठएएळ वक्र 2026 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित हुई ठएएळ UG 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। यह निर्णय कथित पेपर लीक और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद लिया गया है।

परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर में लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत कई शहरों में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है।

NTA ने क्यों रद्द की NEET परीक्षा?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार, 12 मई को जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। एजेंसी के मुताबिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त जांच रिपोर्ट और NTA की आंतरिक समीक्षा में यह सामने आया कि परीक्षा प्रक्रिया से समझौता हुआ हो सकता है।

NTA की सफाई: इनकन्वीनियंस के लिए खेद, लेकिन शुचिता जरूरी

NTA ने स्वीकार किया कि परीक्षा दोबारा कराने से छात्रों और उनके परिवारों को भारी असुविधा होगी। NTA ने अपने बयान में कहा-"भारत सरकार की मंजूरी के बाद NTA ने 3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षा प्रक्रिया को जारी रहने देना उचित नहीं होगा।"

NTA ने बताया कि उसने 8 मई को ही मामले को केंद्रीय एजेंसियों के पास स्वतंत्र जांच और सत्यापन के लिए भेज दिया था।इसके बाद जांच एजेंसियों से मिली रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया।

परीक्षा से एक रात पहले लीक हुआ था पेपर?

सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि NEET UG 2026 का प्रश्नपत्र परीक्षा से एक रात पहले कुछ लोगों तक पहुंच गया था। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कथित प्रश्नपत्र वायरल होने की बातें सामने आई थीं। हालांकि एजेंसियां अभी यह जांच कर रही हैं कि-पेपर वास्तव में कब और कैसे लीक।

किन राज्यों में नेटवर्क सक्रिय था, क्या इसमें संगठित गिरोह शामिल था और कितने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचा है। इन्हीं आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए उइक जांच के आदेश दिए हैं।

अब दोबारा होगी परीक्षा, छात्रों से नहीं लिया जाएगा अतिरिक्त शुल्क

NTA ने स्पष्ट किया है कि NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। मई 2026 चक्र के लिए जमा किए गए सभी आवेदन, उम्मीदवारों का डेटा और परीक्षा केंद्रों की जानकारी आगे भी मान्य रहेगी।

पंजाब पुलिस का हाईटेक ICCC बना आधुनिक पुलिसिंग का नया मॉडल, एआई से अपराधियों पर कड़ी नजर

पंजाब पुलिस ने आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपराध नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को नई दिशा दी है। राज्यभर में

स्थापित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) अब अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने, संदिग्धों की पहचान करने और बड़ी वारदातों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा रहा है। लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों में हाई-रेजोल्यूशन कैमरों और एआई आधारित निगरानी प्रणाली ने पुलिसिंग को और अधिक तेज, स्मार्ट और प्रभावी बना दिया है।

नीट परीक्षा रद्द पर 'आप' का केंद्र के खिलाफ मोर्चा, केजरीवाल बोले- पेपर लीक होना बच्चों के साथ क्रूर मजाक

(जीएनएस)।

ठएएळ 2026 ढंस्त्री१ छीं: नीट परीक्षा 2026 के रद्द होने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने एक साझा बयान में इसे करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा धोखा बताया है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक संभव नहीं है। पार्टी ने मांग की है कि शिक्षा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो और युवाओं को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना होगा।

राजनीतिक संरक्षण में हो रहा पेपर लीक: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान चार बार नीट का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन आज तक किसी बड़े आरोपी को सजा

नहीं मिली। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पहले परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि गरीब माता-पिता अपनी जमीन और गहने गिरवी रखकर बच्चों को कोचिंग कराते हैं, ऐसे में पेपर लीक होना उनके साथ क्रूर मजाक है। उन्होंने युवाओं से जन आंदोलन करने की अपील की है।

भाजपा युवाओं की बबार्दी की गारंटी: संजय सिंह

सांसद संजय सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लिए पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होना भी अब 'देशभक्ति' बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक कराने वाली कंपनियां भाजपा से जुड़ी हुई हैं। सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा बेरोजगार होकर भटकें ताकि उन्हें नफरत और दंगों की राजनीति में झोंका जा सके।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज लखनऊ में सीएम योगी की पहली बड़ी बैठक, सभी मंत्रियों की होगी मौजूदगी

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर सुबह 10:45 बजे एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और सभी राज्य मंत्री शामिल होंगे।

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी बुधवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर सुबह 10:45 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा सभी राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह नई कैबिनेट की पहली संयुक्त बैठक होगी, जिसमें सभी सदस्य एक साथ शामिल होंगे।

10 मई को हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार

बता दें कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार रविवार (10 मई) को संपन्न हुआ। जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छह नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा शामिल हैं। इसके अलावा सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को पदोन्नति दी गई है।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ बदलाव

इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा ने जातीय संतुलन साधने की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए इस बदलाव को पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा का उद्देश्य जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ संगठन और सहयोगी नेताओं को भी साधकर अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करना है।

कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस विस्तार के तहत भूपेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी से आए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही दो मंत्रियों को पदोन्नति भी दी गई है। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब आज नई कैबिनेट की पहली संयुक्त बैठक होगी, जिसपर सभी का ध्यान है।

यूपी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का कमाल: महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश का 'योगी मॉडल' बना देश में नंबर-1

उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 76.6 प्रतिशत की ऐतिहासिक दोषसिद्धि दर (कन्विक्शन रेट) हासिल कर देश के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब आंकड़ों में साफ दिखने लगा है. एनसीआरबी 2024 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 76.6 प्रतिशत की ऐतिहासिक दोषसिद्धि दर (कन्विक्शन रेट) हासिल कर देश के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि दशार्ती है कि राज्य में न केवल अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा कर उन्हें सजा भी दिलाई जा रही है.

मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सीमा कुशवाहा की सराहना

देश के चर्चित निर्भया मामले की वकील और समाज सुधारक सीमा कुशवाहा ने इन आंकड़ों पर खुशी जताते हुए योगी सरकार की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की है.उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से इतने बड़े और जटिल भौगोलिक स्थिति वाले राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. सीमा कुशवाहा के अनुसार, यूपी ने अपराधियों को रिकॉर्ड स्तर पर

सजा दिलाकर देश भर में त्वरित न्याय का एक 'उत्तर प्रदेश मॉडल' पेश किया है, जो अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है.

6 मिनट 52 सेकेंड का वो रोमांटिक गाना...जिसने दशकों पहले लोगों को दीवाना बनाया, 70 साल बाद भी कम नहीं हुआ जादू; खूब गुनगुनाते हैं लोग

19 द्रल्ल४३ी 34 रीङ्गल्ल्ला श्रींङ्ग हो या रङ्गा' रङ्गल्लं'... मत ढूंढिए, वरना बुरा फंसेंगे! ये है वायरल लिंक का खौफनाक सच

सुरक्षा के लिए उठाए गए कड़े कदम

राज्य की इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं. सरकार ने न केवल एंटी-रोमियो स्क्वाड जैसे जमीनी अभियानों के जरिए महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा किया, बल्कि त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना कर कानूनी प्रक्रिया को भी गति प्रदान की. इसके साथ ही, अभियोजन पक्ष को आधुनिक तकनीक और डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से लैस किया गया, जिससे साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को बचना मुश्किल हो गया है. पुलिस की जवाबदेही तय करने और अभियोजन पक्ष को मजबूत करने से समाज में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा है.

विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति

आंकड़ों का विश्लेषण करें तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य प्रमुख राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है. जहां उत्तर प्रदेश 76.6 प्रतिशत की दर के साथ शिखर पर है, वहीं तमिलनाडु 23.4 प्रतिशत और पंजाब 19 प्रतिशत के साथ काफी नीचे हैं. शिक्षित राज्यों की श्रेणी में आने वाले केरल में यह दर मात्र 17 प्रतिशत है, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में यह क्रमशः 14.8 और 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई है. पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे चिंताजनक है, जहां मात्र 1.6 प्रतिशत मामलों में ही सजा हो पा रही है.

सबकी सुरक्षा का संकल्प

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सिद्ध कर दिया है कि 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ 'सबकी सुरक्षा' सुनिश्चित करना ही सुशासन की असली पहचान है. सीमा कुशवाहा का मानना है कि जब न्याय निश्चित और त्वरित होता है, तो समाज से भय का माहौल समाप्त होता है. उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देशभर में डिजिटल फॉरेंसिक और अभियोजन क्षमता निर्माण जैसी योजनाओं का विस्तार करें ताकि हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सके.

लखनऊ नगर निगम मामला, हाईकोर्ट सख्त, मेयर-डीएम और नगर आयुक्त की व्यक्तिगत पेशी के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि पार्षद के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए ललित तिवारी को शपथ नहीं दिलाई गई

(जीएनएस)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि पार्षद के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए ललित तिवारी को शपथ नहीं दिलाई गई, तो लखनऊ के मेयर, डीएम और नगर आयुक्त को 13 मई 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति

आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता ललित तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा के साथ अधिवक्ता नदीम मुर्तजा और उत्सव मिश्रा ने पक्ष रखा।

याचिका में कहा गया कि जिला जज द्वारा 19 दिसंबर 2025 को ललित तिवारी को निर्वाचित घोषित किए जाने के बावजूद पांच महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 85 के तहत शपथ नहीं दिलाई गई।

कोर्ट ने आदेश में उल्लेख किया कि डीएम लखनऊ पहले ही 23 जनवरी 2026 और 10 फरवरी 2026 को नगर आयुक्त को चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले की सूचना दे चुके थे। राज्य सरकार ने भी 4 फरवरी 2026 को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शपथ ग्रहण न होना गंभीर विषय माना गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अगली तारीख तक शपथ नहीं दिलाई जाती, तो मेयर, डीएम और नगर आयुक्त अदालत में उपस्थित होकर जवाब दें कि आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला के वायरल वीडियो पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी; 12 पुलिसवाले हटाए

सिपाही सुनील शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तीन वीडियो जारी करते हुए ड्यूटी लगाने के नाम दो-दो हजार रुपये तक वसूली करने का आरोप लगाया था.

(जीएनएस)।

लखनऊ पुलिस लाइंस के सिपाही सुनील शुक्ला के सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइंस में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसका असर देखने को मिल रहा है. ड्यूटी लगाने के नाम पर कथित वसूली के आरोपों के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरक्षी समेत 12 पुलिसकर्मियों को हटा दिया है.

सिपाही सुनील शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तीन वीडियो जारी करते

हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि गार्ड ड्यूटी लगाने के नाम पर सिपाहियों से प्रति व्यक्ति दो-दो हजार रुपये तक वसूले जाते हैं. यह रकम चैन सिस्टम के जरिए ऊपर तक पहुंचती है.

जिसके बाद ये मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पुलिस कमिश्नरेट ने इन वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए है. लखनऊ पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल से जानकारी दी गई है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए गणना कार्यालय में तैनात 12 पुलिसकर्मियों को हटाकर उनकी जगह नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई हैं.

अब कंप्यूटर से लगाई जाएगी ड्यूटी

इस पूरे विवाद के बाद सबसे बड़ा बदलाव ड्यूटी आवंटन प्रक्रिया में किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब गणना कार्यालय में कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली लागू की जाएगी. इससे ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया डिजिटल होगी और मानव हस्तक्षेप कम किया जाएगा.

दरअसल, सुनील शुक्ला ने अपने वीडियो में आरोप लगाया था कि ड्यूटी आवंटन में पूरी तरह सेटिंग और वसूली की जाती है. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग पर पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है. सिपाही ने एक और वीडियो जारी कर उसके परिवार को भी परेशान करने का आरोप लाया है. हालांकि पुलिस ने इस तरह के आरोपों से इनकार कर दिया है.

इस मामले की जाँच की जा रही है. जांच कमेटी ने कहा कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

पल्लवी ने मुझे पागल कर दिया लखनऊ में सैलून मैनेजर ने किया सुसाइड, मौत से पहले वीडियो में खोले बड़े राज

लखनऊ के शालीमार विस्टा अपार्टमेंट में 32 वर्षीय रत्ना सिंह ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सुसाइड नोट जैसे वीडियो में उसने पांच लोगों और एक युवक के परिवार पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं.

(जीएनएस)।

छ४ूल्लङ्क६ ठी६२: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र स्थित शालीमार विस्टा अपार्टमेंट में रहने वाली 32 वर्षीय युवती ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में उसने पांच लोगों और एक युवक के परिवार को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया.

पुलिस के अनुसार, मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली रत्ना सिंह लखनऊ के एक सैलून में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी. सोमवार देर रात उसने अपनी एक परिचित को फोन कर बताया कि वह आत्महत्या करने जा रही है. युवती की दोस्त ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गोमतीनगर विस्तार थाना पुलिस रात करीब 3 बजे शालीमार विस्टा

अपार्टमेंट पहुंची.

पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. अंदर रत्ना सिंह का शव पंखे से लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सुसाइड से पहले वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला, जिसे रत्ना सिंह ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया था. वीडियो में उसने पांच लोगों के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. साथ ही एक युवक के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए.

मृतका रत्ना ने कहा कि, आज मैं सुसाइड करने जा रही हूं. इसके लिए जिम्मेदार शरद सिंह और पल्लवी जोशी होंगी. शरद सिंह ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और पल्लवी जोशी ने मुझे पागल कर दिया. वीडियो में लगाए गए इन आरोपों के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गोमतीनगर विस्तार थाना प्रभारी सुधीर अवस्थी ने बताया कि फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आत्महत्या के कारणों और वीडियो में लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ स्टेशन पर ब्लॉक से 15 मई से 23 जून तक ट्रेनें प्रभावित, 12 का बदला रूट, इधर, कानपुर सेंट्रल के रास्ते से कई जोड़ी विशेष ट्रेनें

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य और पश्चिमी रेलवे में सिग्नल कार्य के कारण 15 मई से 23 जून तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इससे

(जीएनएस)।

कानपुर। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर होने वाले कांकार्स निर्माण और पश्चिमी रेलवे में सिग्नल कार्य के कारण रेल यातायात में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ के समय में बदलाव किया गया है।

छह के समय में बदलाव और 12 ट्रेनों का बदला गया रूट

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कांकार्स निर्माण कार्य किया जाएगा। इसलिए 15 मई से 23 जून तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं प्लेटफार्म संख्या चार पूरी तरह बंद रहेगा और तीन पर भी छह घंटे का रोजाना ब्लाक लिया जाएगा। इसलिए छह ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं 12 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ये ट्रेनें प्रभावित

12 मई से 25 जून तक काम के दौरान झांसी-लखनऊ मेमू (64701) कानपुर सेंट्रल तक ही संचालित की जाएगी।

लखनऊ-झांसी मेमू (64702) कानपुर सेंट्रल से संचालित होगी।

शाहजहांपुर-लखनऊ पैसेंजर (54338) और बालामऊ-लखनऊ पैसेंजर (54332) आलमनगर स्टेशन पर ही समाप्त होंगी।

लखनऊ-शाहजहांपुर पैसेंजर (54337) और लखनऊ-बालामऊ पैसेंजर (54331) आलमनगर से चलाई जाएंगी।

लंबी दूरी की मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस, गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस, कामाख्या-गांधीधाम एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस, भावनगर टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस और पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल मार्ग से संचालित होंगी।

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ठहराव निरस्त

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि इन ट्रेनों का लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ठहराव निरस्त रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। वहीं बरेली-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस (14308) को आलमनगर-ट्रांसपोर्ट नगर-उतरेटिया मार्ग से चलाया जाएगा और इसका भी लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। बताया कि प्लेटफार्म नंबर चार पर रुकने वाली 36 अन्य ट्रेनों को ब्लाक के दौरान अन्य प्लेटफार्म पर रोका जाएगा। इसके अलावा प्लेटफार्म नंबर तीन पर रुकने वाली दो ट्रेनों को भी अन्य प्लेटफार्म पर शिफ्ट कराया जाएगा।

सिग्नल कार्य से कई ट्रेनों के आई परिचालन में बाधा

रेल प्रशासन ने पश्चिमी रेलवे के उधना-चलथान स्टेशनों के बीच स्वचालित सिग्नल कार्य के चलते कई ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण, रेग्यूलेशन और रीशेड्यूलिंग जारी कर दी है। ट्रेन-01908 उधना-आगरा छावनी विशेष गाड़ी, प्रारंभिक स्टेशन से 13 मई को सूरत स्टेशन से चलेगी और सूरत-उधना के मध्य निरस्त रहेगी।

ट्रेन-09075 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम विशेष गाड़ी 13 मई को समय 60 मिनट रीशेड्युल की गई है।

ट्रेन-04155 सूबेदारगंजझउधना प्रारंभिक स्टेशन से 14 मई को समय 35 मिनट रीशेड्युल रहेगी।

ट्रेन-12925 बांद्रा टर्मिनल-अमृतसर एक्सप्रेस और 22917 बांद्रा टर्मिनल-हरिद्वार एक्सप्रेस 60 मिनट और 19046 थाने-सूरत एक्सप्रेस शुरूआती स्टेशन से 13 मई को 90 मिनट रेग्यूलेट की गई है।

ट्रेन-22948 भागलपुर-सूरत एक्सप्रेस शुरूआती स्टेशन से 14 मई को 90 मिनट रेग्यूलेट की गई है।

यहां राहतः खूब घूमिए... सेंट्रल के रास्ते से कई जोड़ी विशेष ट्रेनें

रेल प्रशासन ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखकर कानपुर के रास्ते कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के चलने से न केवल दिल्ली जाने वाली नियमित ट्रेनों में भीड़ कम रहेगी, बल्कि बिहार और उत्तर-पूर्व के राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी सीट मिल सकेगी। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने दी।

उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या-05758 शुक्रवार को न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली से 15:10 पर प्रस्थान करेगी, जो दूसरे दिन शनिवार को 17:35 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह 25 मई को ट्रेन संख्या-05757 नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 1:15 बजे निकलेगी, जो उसी दिन 8:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। ऐसे ही शुक्रवार और सोमवार को न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद विहार टर्मिनल-न्यू जलपाईगुड़ी विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसमें ट्रेन संख्या-05760 न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद विहार टर्मिनल विशेष 22 मई को 12:15 बजे प्रस्थान करेगी, जो 23 मई को 12:25 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पर आएगी। फिर 25 मई को 2:40 बजे ट्रेन संख्या-05759 आनंद विहार से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चलेगी, जो गोविंदपुरी स्टेशन पर 8:45 बजे पहुंचेगी।

20 मई को ट्रेन संख्या-05664 अगरतला से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 15:00 बजे चलेगी, जो 22 मई को 12:15 बजे गोविंदपुरी स्टेशन आएगी। फिर 25 मई को आनंद विहार टर्मिनल से अगरतला के लिए 3:00 बजे चलेगी, जो उसी दिन गोविंदपुरी स्टेशन पर 9:20 बजे पहुंचेगी। ऐसे ही सिलचर-दिल्ली-सिलचर के लिए विशेष ट्रेन संख्या-05666/05665 संचालित की गई है। 21 मई को 20:30 बजे सिलचर से चलकर विशेष ट्रेन 23 मई को गोविंदपुरी स्टेशन पर 15:20 आएगी। जबकि, सिलचर के लिए 25 मई को ट्रेन 02:45 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेगी, जो उसी दिन 08.55 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या-05924/05923 न्यू तिनसुकिया-नई दिल्ली-न्यू तिनसुकिया विशेष गाड़ी का संचालन गुरुवार और सोमवार को हो रहा है। 21 मई को न्यू तिनसुकिया से नई दिल्ली के लिए ट्रेन 12:00 बजे चलेगी, जो 23 मई को 07.10 गोविंदपुरी में आएगी। फिर 25 मई को नई दिल्ली से न्यू तिनसुकिया के लिए ट्रेन 02:50 बजे चलेगी। यह ट्रेन गोविंदपुरी में उसी दिन 09.10 बजे आएगी। डिब्रूगढ़-नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के लिए गुरुवार और सोमवार को ट्रेन संख्या-05926/05925 संचालित हो रही है। 21 मई को डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के लिए ट्रेन 18:00 बजे चलेगी, जो 23 मई को 15.50 बजे गोविंदपुरी स्टेशन आएगी। लौटते समय 25 मई को नई दिल्ली से ये ट्रेन 03:10 बजे चलेगी और गोविंदपुरी में उसी दिन 09.30 बजे पहुंचेगी।

नाहरलगुन से नई दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन

गुरुवार और सोमवार को विशेष ट्रेन नाहरलगुन से नई दिल्ली के आवागमन के लिए संचालित हुई है। यह 21 मई को ट्रेन नाहरलगुन से 22.15 बजे चलेगी, जो 22 मई को गोविंदपुरी स्टेशन पर 06.10 बजे आएगी। फिर 25 मई को नई दिल्ली से 03:50 बजे चलेगी, जो गोविंदपुरी में 09.55 बजे आएगी।

शोरूम महिला कर्मचारी और पूर्व एमआर ने फंदे से लगाकर दी जान

(जीएनएस)।

लखनऊ, पारा और पीजीआई क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाओं में शोरूम की महिला कर्मचारी और पूर्व एमआर ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस को दोनों ही मामलों में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शोरूम कर्मचारी के मामा ने पुलिस से जांच की मांग की है।

इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह के मुताबिक बाराबंकी के अनियारी इस्लामपुर निवासी अंजलि तिवारी (22) दो वर्षों से पारा के मॉडल सिटी में किराये पर रहती थीं। वह आलमबाग स्थित बाइक शोरूम में काम करती थीं। मकान मालिक ने बताया कि उनका बेटा रात 12:00 बजे घर लौटा तो उसकी नजर अंजलि के कमरे की खिड़की पर पड़ी। उसने अंजलि को दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका देखा। दरवाजा तोड़कर अंजलि को फंदे से उतारा गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सोमवार सुबह चार बजे सूचना पर पहुंची पुलिस और

फोरेंसिक टीम ने जांच की और अंजलि का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। उनके मामा शिवम दुबे ने मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने की मांग की है। अंजलि के परिवार में पिता दुर्गेश और भाई निखिल हैं। मां की वर्ष 2023 में बीमारी के चलते मौत हो गई थी।

वहीं, मूलरूप से देवरिया के रहने वाले पूर्व एमआर पीयूष मणि त्रिपाठी (35) पीजीआई के कैलाश एन्क्लेव में पत्नी खुशबू और तीन वर्षीय बेटी ईरा के साथ रहते थे। खुशबू केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, पीयूष और उनकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। रविवार को खुशबू किसी काम से बेटी के साथ बाहर गई थीं। घर में पीयूष थे। शाम को फोन का जवाब न मिलने पर खुशबू ने पड़ोसी को कॉल कर पति से बात कराने की बात कही। पड़ोसी जब घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो पीयूष पंखे से दुपट्टे के सहारे लटके मिले। इंस्पेक्टर ने बताया कि घरवालों ने अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

भारत में जैविक आतंक पैलाने की एक बड़ी साजिश का पदार्फाश

प्रयोगशालाओं में जीन परिवर्धित करके जो विषाणुजीवाणु अस्तित्व में लाए जा रहे हैं, हो सकता है, उनके तोड़ के लिए किसी के पास एंटीबा योटिक एवं एंटी- वायरल ड्रग्स ही न हों? दरअसल मानव निर्मित वायरस इसलिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसे पहले से उपलब्ध वायरस से ज्यादा खतरनाक बनाया जाता है।

भारत पर मंडरा रहा है जैविक आतंकवाद का खतरा जैविक आतंकवाद अब प्रामाणिक सच्चाई में बदलता दिखाई देने लगा है। भारत में जैविक आतंक पैलाने की एक बड़ी साजिश का पदार्फाश हुआ है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मई 2026 में तीन लोगों के विरुद्ध अहमदाबाद गुजरात की विशेष एनआईए अदालत में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। इस षडांत्र में हैदराबाद के मुख्य आरोपी डॉ सैयद अहमद मोहिउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसने अपने घर में ही एक घातक जैविक विष बनाने की प्रयोगशाला बना ली थी। इसे अरंडी के बीज से तैयार किया जाता है। इस मामले में सहयोगी आरोपी उप्र के आजाद और मोहम्मद सुहेल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी आतंकी संगठन आइएस आइएस से जुड़े विदेशी आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे थे। इनका लक्ष्य भारत में भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर जैविक जहर पैलाने का था। फलों, सब्जियों और मंदिरों के प्रसाद में भी जहर मिलाकर हमला करने की साजिष रच रहे थे। ये ऐसी आतंकी घटनाओं को दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ में अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस ने भी मई माह में आईएसआई के 9 एजेंटों को देष के विभिन्न नगरों से हिरासत में लिया है। ये गिरफ्तारियां इस बात का ठोस सबूत हैं कि आतंकी भारत में जैविक हमला करने की तैयारी में लगे हैं।

वृत्रिम बुद्धिमत्ता से जैविक हथियार बनाना हुआ आसान - वृत्रिम बुद्धि की उपलब्धियां अब केवल नौकरी, पढ़ाई और तकनीक तक सीमित नहीं रह गईं है। जैविक सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों को आशंका है कि एआई भविष्य में जैविक आतंकवाद को भी आसान बना सकता है। कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक विशेषज्ञता हासिल किए बिना बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुविष् णु एवं किटाणु बनाकर उन्हें बड़े समूहों में पैला सकता है। हाल के दिनों में जीन या आनुवंशिक अनुव्रमण (जेनेटिक सीक्वेंस, सीआरआईएसपीआर यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड षॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स) जैसी व्रांतिकारी जीन संपादन तकनीक से जीवित जीवों के डीएनए को मनचाहे रूप में परिवर्धित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये बायोलॉजीकल इंजीनियरिग टूल किट्स बाजार में उपलब्ध होने लगे है। प्रयोग में लाए जाने वाले कई औजार और अन्य सामग्री ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदे जा सकते है। इससे हानि नहीं पहुंचाने वाले जीवाणुओं को जानलेवा घातक बनाया जा सकता है। इनके निर्माण में एआई के समय में विकसित हुए लार्ज लैंग्वेज मशीन (एलएलएम) मॉडल को प्रयोग में लाया जाता है। यह एक प्रकार की वृत्रिम बुद्धि है। इससे इंसानी भाषा को समझने, सारांशित और अनुवादित करके एआई पाठ को वंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत कर देता है। ये वंप्यूटर मशीन, लर्निग और न्यूरल नेटवर्व का उपयोग करते हैं। अतएव यह तकनीक इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा से संदर्भ एकत्रित कर इंसान से संवाद करने में सक्षम है। इसी तकनीक से आतंकी जैविक हथियार बनाने के उपाय में लगे हैं। विशेषज्ञों की चिता - किसी भी वैज्ञानिक तकनीक के अनुचित उपयोग के परिप्रेक्ष्य में विशेषज्ञों का चितित होना स्वाभाविक है। क्योंकि जैविक हथियार बनाने की विधियां ओपन एआई और गूगल जैसे प्लेटफार्म पर सुलभ हैं। हालांकि इस संदर्भ में यह एक अच्छी बात है कि एलएलएम के प्रयोग बड़ी संख्या में गड़बड़ा जाते हैं। फिर भी तकनीकी जानकारी की आसान उपलब्धता से अनेक यूजर इस तकनीक को सीखने में लगे रहें, तो वे विशेषज्ञ बन सकते हैं। एआई वंपनियां भी अब इस बात को स्वीकारने लगी हैं कि उनके मॉडल मामूली विज्ञान संबंधी ज्ञान रखने वाले जिज्ञासु की जैविक हथियार बनाने में मदद करने में सहायक होते है।

यूपी की राज्यपाल की नातिन बनीं श्रीकृष्ण की 'सत्यभामा', सीएम योगी ने दिया सम्मान, संस्कृति का सादा रूप जीत गया दिल

उत्तर प्रदेश में फिल्म 'कृष्णावतारम' के टैक्स फ्री होने के बाद से ही इसकी लीड हीरोइन के चर्चे तेज हो गए हैं, जिन्हें सीएम योगी ने सम्मानित किया। जहां वह अपनी नानी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बगल में खड़े होकर बेहद खुश नजर आईं, तो उनकी सादगी भी सबका दिल जीत गई।

कृष्णावतारम की संस्कृति का स्टाइल छाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को फिल्म 'कृष्णावतारम भाग 1: हृदय (हृदयम)' देखने के बाद उसे राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन 'श्रीकृष्ण' की पटरानी 'सत्यभामा' का किरदार निभाकर सबका दिल जीत गई हैं। जिन्हें पूरी कास्ट के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सीएम योगी ने सम्मान में श्रीकृष्ण की प्रतिमा भेंट की, तो उनके चेहरे की खुशी और सादे-सिंपल रूप ने दिल जीत लिया।

दरअसल, फिल्म में संस्कृति पटेल 'सत्यभामा' के किरदार में नजर आई हैं, जो आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की बेटी यानी उनकी नातिन हैं। जिनकी फिल्म में दमदार एक्टिंग के साथ ही प्रमोशनल इवेंट्स

के दौरान स्टाइलिश लुक्स को भी लोग पसंद कर रहे हैं। तभी तो जब वह यहां इंडो वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस में नजर आईं, तो उनका अंदाज सबको भा गया। (फोटो साभार: इंस्टाग्राम

स्क्रीनिंग के लिए सादे- सिंपल लुक में दिखे सब

मूवी की स्क्रीनिंग के लिए कास्ट सहित सभी लोग फॉर्मल एथनिक और इंडो- वेस्टर्न लुक में नजर आए। मेन लीड सिद्धार्थ और संस्कृति ने कुर्ता और अनारकली स्टाइल गाउन में अपना स्टाइलिश रूप दिखाया, तो सीएम योगी हमेशा की तरह भगवा अंदाज में दिखे। वहीं, आनंदीबेन पटेल खूबसूरती-सी रेड सिल्क साड़ी पहने नजर आईं। जिसके पल्लू और बॉर्डर पर ब्लू कलर से फ्लोरल और बेल जैसा पैटर्न बना है, तो साथ में ब्लू प्लेन ब्लाउज पहना। जहां उनके चेहरे पर नातिन की पहली फिल्म की खुशी साफ दिखी।

एलिगेंट लगा संस्कृति का अंदाज

एलिगेंट लगा संस्कृति का अंदाज

हालांकि, यहां हम राज्यपाल की नई- नई हीरोइन बनी नातिन संस्कृति के लुक की डिटेल्स पर गौर करेंगे, जहां उनका इंडो- वेस्टर्न लुक बेहद एलिगेंट और सॉफ्ट फेमिनिन वाइब दे रहा है। अनियन पिंक शेड के फ्लोर लेंथ अनारकली स्टाइल गाउन में वह बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं। आउटफिट का फ्लोई सिल्हूट और शाइनी फैब्रिक स्टेज की लाइट्स के बीच और हाइलाइट हो रहा, जबकि मिनिमल स्टाइलिंग ने उनके लुक को क्लासी बनाए रखा।

सेक्विन और एम्ब्रॉयडरी से सजा अपर पोर्शन

इस वन-पीस एंसेंबल में वेस्ट पर हल्का फिटेड पैटर्न दिया गया, जिससे स्कर्ट और टॉप जैसा इल्यूजन बन रहा है। अपर पोर्शन पर बारीक एम्ब्रॉयडरी और टेक्सचर्ड डिजाइन नजर आया, जो आउटफिट को रिच फील दे रहा है। जिसमें सेक्विन के साथ थ्रेड वर्क का यूज किया, जो पूरे अपर पोर्शन को हैवी टच दे रहा है। वहीं, आउटफिट की सबसे स्टाइलिश चीज इसकी ड्रामेटिक बेल स्लीव्स रही। ढीली और फ्लेयर्ड स्लीव्स ने पूरे लुक में मॉडर्न टच जोड़ा।

फ्लेयर्ड स्कर्ट पोर्शन लगा बढ़िया

वहीं, संस्कृति के अनारकली स्टाइल गाउन के स्कर्ट पोर्शन को खूब सारी फ्लेयर्ड ऐड करके घेरदार बनाया। जिसके प्लीट्स और फ्लोई टेक्सचर इसे ट्रेडिशनल अनारकली स्टाइल वाली फील के साथ लॉन्ग स्कर्ट जैसा टच दे रहे हैं। जिस पर कोई भी वर्क नहीं किया गया, तभी तो यह पूरे लुक में बैलेंस लाने के साथ ही उन्हें सॉफ्ट और स्टनिंग लुक दे रहा है। जिसे हसीना ने बड़े- ही ग्रेस के साथ कैरी किया।

नीट पेपर लीक पर भड़के सुपर 30 वाले आनंद कुमार, सरकार से कर दी चीन जैसे कौन से मॉडल की मांग?

(जीएनएस)।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने से लाखों छात्र और उनके परिवार चिंता में हैं। इसी बीच सुपर 30 के संस्थापक और मशहूर शिक्षक आनंद कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कठिन समय में घबराने के बजाय खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। आनंद कुमार का यह बयान ऐसे समय आया है जब देशभर में छात्र दोबारा परीक्षा की तैयारी को लेकर मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं।

छात्रों को हिम्मत न हारने की सलाह

आनंद कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि NEET परीक्षा में पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने माना कि परीक्षा रद्द होने की खबर छात्रों और उनके माता-पिता के लिए निराशाजनक है, लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया।

ये भी पढ़ें: कौन है ठएएळ वऋ पेपर लीक का मास्टरमाइंड राकेश मंडावरिया? पत्नी है सरपंच, परिवार में कौन-कौन?

उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में छात्रों को निराश होकर बैठने के बजाय नए जोश के साथ तैयारी शुरू करनी चाहिए। उनके मुताबिक मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जो छात्र लगातार ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी।

NEET की परीक्षा में पेपर लीक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए यह खबर निश्चित रूप से निराश करने वाली है। फिर भी थोड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने परीक्षा रद्द करते हुए तुरंत ही दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है।

'हर चुनौती के बाद नया मौका आता है'

सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने छात्रों से सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है और यही समय मानसिक रूप से मजबूत रहने का है। उन्होंने छात्रों से कहा कि डर और घबराहट में आने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें।

आनंद कुमार ने यह भी कहा कि लाखों छात्र कई महीनों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसलिए अचानक परीक्षा रद्द होने से तनाव होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे समय में संयम और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

अपने बयान में आनंद कुमार ने सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते रहेंगे तो इसका असर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए जांच एजेंसियों को तेजी और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने चीन के गाओकाओ परीक्षा सुधारों का उदाहरण दिया, जहां प्राइवेट कोचिंग पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, परीक्षा केंद्रों पर एडवांस्ड एंटी-चीटिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है और पूरे परीक्षा प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। चीन ने वर्ष 2021 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में निजी कोचिंग सेक्टर पर सख्त नियम लागू किए थे। वहां मुख्य विषयों की कमाई वाली ट्यूशन सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी, जबकि छुट्टियों के दौरान चलने वाली कोचिंग कक्षाओं को भी बंद कर दिया गया।

इसके साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए एआई आधारित निगरानी, प्रश्न पत्रों की कड़ी सुरक्षा और नकल रोकने वाली आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आनंद कुमार का कहना है कि भारत में भी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए इसी तरह की सख्त जवाबदेही तय करना जरूरी है।

'डिबेट करते-करते दिल हार बैठे थे शिक्षा मंत्री', कौन हैं पत्नी मृदुला ठाकुर?

(जीएनएस)।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला कथित गेस पेपर, सवालों के लीक होने और बड़े स्तर पर छात्रों तक सामग्री पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है,जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया है, जिसतकी वजह सेनेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने NEET वऋ परीक्षा के मुद्दे पर मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल दिल्ली में इसे लेकर हंगामा जारी है, इसी हंगामे के बीच जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान की लवस्टोरी के बारे में जो कि काफी दिलचस्प और फिल्मी है।

आपको बता दें कि अक्सर अपनी बातों से विरोधियों को चारों खाने चित्त करने वाले धर्मेंद्र प्रधान हिमाचल की मृदुला ठाकुर पर पहली नजर में ही फिदा हो गए थे। 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में जन्में धर्मेंद्र प्रधान असल में हिमाचल के जमाई बाबू हैं।

ओडिशा के धर्मेंद्र प्रधान को हिमाचली मृदुला से हुआ था प्यार

दरअसल हिमाचल के कोठुवां गांव की रहने वाली बेहद ही खूबसूरत लेकिन तेज तर्रार मृदुला ठाकुर हिमाचल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेता थीं। मुंबई के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तेज तर्रार धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात मृदुला ठाकुर से हुई थी।

मृदुला के बोलने के अंदाज पर फिदा हो गए थे धर्मेंद्र प्रधान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त स्टेज पर किसी गहन विषय पर डिबेट चल रही थी, मंच पर धर्मेंद्र और मृदुला दोनों थे, जहां धर्मेंद्र युवा मृदुला के तर्क, बोलने के अंदाज पर फिदा हो गए थे। वो पहली नजर में मृदुला ठाकुर की छात्र राजनीति से प्रभावित हो गए थे। दोनों में मित्रता हुई और फिर लगा कि दोनों जीवन की

नैया एक साथ चला सकते हैं। साल 1998 में इन्होंने परिवार वालों की सहमति से शादी कर ली, इस शादी से दोनों को दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं।

शादी के बाद मृदुला ठाकुर ने लिया राजनीति से ब्रेक

शादी के बाद मृदुला ने राजनीति से ब्रेक लिया और घर-परिवार में जुट गईं लेकिन पति के साथ वो अक्सर राजनीतिक मंच पर नजर आती हैं, यही नहीं वो बहुत सारे सोशल इवेंट में भी व्यस्त रहती हैं। अपने नाम के अनुरूप ही वो स्वभाव से भी मृदुल हैं और पति के हर सुख-दुख में साए की तरह साथ रहती हैं, दोनों राजनीति के परफेक्ट कपल कहलाते हैं।

राजनीति विरासत में मिली

गौरतलब है कि धर्मेंद्र को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता देवेंद्र प्रधान, वाजपेयी सरकार (1998-2004) में पूर्व राज्य मंत्री थे। 1983 में तालचेर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अइश्द) के माध्यम से छात्र राजनीति में सक्रिय हुए, उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष और बाद में सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय से मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की।

2021 से शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल रहे

साल 2000 में धर्मेंद्र प्रधान पल्लाहारा से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं, वो जुलाई 2021 से शिक्षा

हिमंत बिस्वा सरमा शपथ समारोह: पीएम मोदी-सुवेंदु मौजूद, हथियारबंद शातिर अरेस्ट, निशाने पर कौन? 6 दिन में तीसरी वारदात

(जीएनएस)।

असम के सियासत के नए पन्ने पर 12 मई 2026, आज एक नया अध्याय जुड़ गया। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में एक भव्य समारोह के बीच हिमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनकी लगातार दूसरी पारी है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें और चार अन्य विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सबानंद सोनोवाल समेत इखढ शासित राज्यों के दर्जनों मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री और इखढ अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे।

सुवेंदु अधिकारी (पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री) की मौजूदगी ने इस समारोह को खास राजनीतिक रंग दिया। शपथ ग्रहण से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगने की कोशिश सामने आई, जब एक व्यक्ति

को जिंदा गोलियां लेकर पकड़ा गया। यह घटना 6 दिनों में तीसरी बड़ी सुरक्षा वारदात है। आपको बता दें कि, 6 मई को सुवेंदु के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या और 10 मई को बेंगलुरु में PM मोदी के कार्यक्रम के पास जिलेटिन स्टिक्स की बरामदगी हुई थी। यह समारोह महज शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर में BJP की रणनीतिक मजबूती, हिमंत की विकास-विरोधी घुसपैठ नीति और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों का प्रतीक बन गया।

NDA का रिकॉर्ड प्रदर्शन

126 सदस्यीय असम विधानसभा में ठऊअ ने 102 सीटें जीतीं। BJP अकेले 82 सीटों के साथ बहुमत से काफी आगे रही। सहयोगी AGP और BPF ने 10-10 सीटें हासिल कीं। यह BJP के लिए लगातार तीसरी जीत है। हिमंत बिस्वा सरमा ने जलुकबारी सीट से शानदार जीत दर्ज की।

अजंता नेओग (BJP, पूर्व वित्त मंत्री)

रामेश्वर तेली (BJP, पूर्व केंद्रीय मंत्री)

अतुल बोरा (AGP)

चरण बोरो (BPF)

तीन ने असमिया भाषा में और एक ने बोडो भाषा में शपथ ली। हिमंत ने धोती-कुर्ता और पारंपरिक गमोसा पहनकर असमिया संस्कृति का प्रतीकात्मक सम्मान किया।

हिमंत बिस्वा सरमा: जमीन से जुड़े रणनीतिकार, हिमंत बिस्वा सरमा असम की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं। कांग्रेस से BJP में आने के बाद उन्होंने राज्य को नई दिशा दी। उनकी पहली सरकार में CAA-NRC, घुसपैठ पर सख्ती, आर्थिक विकास, सड़क-बुनियादी ढांचा और युवा रोजगार पर फोकस रहा।

मुख्य उपलब्धियां (2021-2026): घुसपैठ पर प्रभावी अंकुश (BJP का दावा: असम-त्रिपुरा में समस्या लगभग खत्म)। बोडोलैंड और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में शांति। कृषि, चाय उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा। मां कामाख्या मंदिर विकास और शंकरदेव की विरासत को प्रोत्साहन।

शपथ के बाद हिमंत ने पर लिखा कि मां कामाख्या, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और असम की जनता के आशीर्वाद से मैंने शपथ ली है। हम जनता की सेवा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने सुवेंदु अधिकारी ने हिमंत बिस्वा के शपथ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने मां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की और कहा कि हिमंत जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनके काम करने के तरीके से मैं बहुत कुछ सीखता हूं। असम-ओडिशा-बिहार-सिक्किम जैसे राज्य मिलकर नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत का विकास करेंगे। सुवेंदु ने घुसपैठ पर असम मॉडल की तारीफ की और कहा कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तर्ज पर कदम उठाए जाएंगे। यह बयान BJP की रणनीति का संकेत है, बंगाल में सत्ता हासिल करने के बाद पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में समन्वय बढ़ाना।

6 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं

12 मई- गुवाहाटी शपथ समारोह: शपथ से कुछ मिनट पहले सुरक्षा जांच के दौरान एक व्यक्ति को जिंदा गोलियां लेकर पकड़ा गया। बसिष्ठा पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। हालांकि हथियार नहीं मिला, लेकिन जांच में सुरक्षा खतरे की आशंका जताई जा रही है। PM मोदी, अमित शाह समेत सैकड़ों VIP मौजूद थे।

10 मई - बेंगलुरु: PM मोदी के कार्यक्रम स्थल के करीब 3 किमी दूर जिलेटिन स्टिक्स बरामद। धमाका टाला गया।

6 मई- सुवेंदु के PA की हत्या: 4 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजों में इखढ की प्रचंड जीत के दो दिन बाद 6 मई को मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ (सुवेंदु के निजी सहायक) की गोली मारकर हत्या की दी गई। प्रोफेशनल किलिंग मानी जा रही है। रक्ळ ने यूपी-बिहार से शार्पशूटर्स गिरफ्तार किए। BJP इसे TMC का बदला बता रही है।

हें कहा गया 'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी'? एक्टर संग कैसी दोस्ती? मचा हंगामा

(जीएनएस)।

तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के सामने आने के बाद से इंटरनेट पर हलचल मच गई है। दरअसल कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ सीरत कपूर की दोस्ती को लेकर आपत्तिजनक और महिला-विरोधी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं।

सीरत कपूर इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वजह बनी है उनकी एक ऐसी प्रतिक्रिया, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। हालांकि इस बार सीरत कपूर ने चुप रहने के बजाय ट्रोलर्स को सीधे और सख्त अंदाज में जवाब दिया है। एक्ट्रेस का ये जवाब अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी बेबाकी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

-जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला गत 8 अप्रैल 2026 से जुड़ा है जब सीरत कपूर ने अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर उनके साथ कुछ खास तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में दोनों प्राइवेट जेट में नजर आ रहे थे। इस पोस्ट के साथ सीरत ने एक्टर के लिए एक इमोशनल मैसेज भी लिखा था और उन्हें बेहद जमीन से जुड़ा इंसान बताया था।

-इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई लोगों को पहली बार पता चला कि सीरत कपूर और अल्लू अर्जुन अच्छे दोस्त हैं। जहां कई फैंस ने इस दोस्ती की तारीफ की, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर घटिया टिप्पणियां शुरू कर दी थीं।

'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी' कहने पर भड़कीं सीरत

-हाल ही में सीरत कपूर ने लेसी ब्राउन आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे थे लेकिन इसी दौरान एक यूजर ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें 'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी' कह दिया। इस कमेंट को पढ़ते ही सीरत कपूर ने यूजर को करारा जवाब दिया।

-सीरत कपूर ने लिखा कि सिर्फ दिल वाली इमोजी लगाने से कोई बात सम्मानजनक नहीं हो जाती। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी महिला किसी की संपत्ति नहीं होती।

हर महिला की अपनी पहचान, अपने सपने और अपनी आवाज होती है। एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि महिलाओं की तारीफ सम्मान के साथ करनी चाहिए, उन पर मालिकाना हक जताने वाले अंदाज में नहीं।

-सीरत कपूर के इस जवाब को सोशल मीडिया पर खूब समर्थन मिल रहा है। कई यूजर्स ने उनके कमेंट को लाइक किया है और ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया है। फैंस का कहना है कि एक्ट्रेस ने बेहद जरूरी मुद्दे पर आवाज उठाई है और महिलाओं को लेकर इस तरह की सोच पर रोक लगनी चाहिए।

-एक फैन ने लिखा है कि सीरत कपूर हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करती हैं और उन्हें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं कई लोगों ने उनके जवाब को सटीक और बोल्ड बताया है।

सीरत कपूर एक एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर और कोरियोग्राफर हैं। वह मुख्य रूप से तेलुगू सिनेमा में एक्टिव हैं लेकिन बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर की थी। साल 2014 में सीरत कपूर तेलुगू फिल्म 'रन राजा रन' से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसी साल वह हिंदी फिल्म 'जिद' में भी नजर आई थीं। बाद में उन्होंने कई तेलुगू फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया था।

बीएचयू में सोमनाथ स्वाभिमान आध्यात्मिक संगोष्ठी में शामिल हुए देशभर के संत-महात्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया संबोधित

(जीएनएस)।

वाराणसी : 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, अटूट आस्था की गौरव गाथा' के अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति के भव्य समारोह का आयोजन सोमनाथ में किया गया है। इसी उपलक्ष्य में मंगलवार को संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन ने आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में देशभर के प्रमुख संत-महात्माओं ने भाग लिया। संगोष्ठी का आयोजन दोपहर दो बजे से बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में किया गया। इस सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराएं विश्व में अद्वितीय हैं। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का इतिहास केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ धर्म के स्तंभ हैं, उन्होंने कहा कि सरकार संतों के मार्गदर्शन में समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना है। संतों ने अपने विचारों के माध्यम से समाज में एकता,

भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। संगोष्ठी में उपस्थित संतों ने कहा कि आज के समय में आध्यात्मिकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने युवाओं को सही मार्ग पर चलने और अपने जीवन में नैतिकता को अपनाने की प्रेरणा दी।

इस संगोष्ठी में देशभर के प्रमुख संतों में आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हरिद्वार के स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से स्वामी रामदेव और साध्वी देवप्रिया, परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी नारायण गुजरात के भद्रेश दास महाराज, दिव्य सेवा मिशन हरिद्वार के डा. आशीष गौतम, अयोध्या के जगदगुरु वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर महाराज, सिद्धपीठ हनुमन्निवास के मिथिलेश नंदिनी शरण, महामंडलेश्वर कैलाश मठ काशी निरंजनी अखाड़ा के आशुतोषानंद गिरि, धर्मसंघ पीठाधीश्वर काशी के स्वामी शंकर चैतन्य ब्रह्मचारी, बिहार के स्वामी विश्वंभर दास, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक, बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. एके त्यागी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा आदि भी अपने विचार रख रहे हैं।

आने वाले समय में कई राष्ट्र सनातन को स्वीकार करेंगे: बाबा रामदेव

योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज देश के 70 प्रतिशत हिस्से में भगवा है। आने वाले समय में कई राष्ट्र सनातन को स्वीकार करेंगे। बाबा रामदेव सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित आध्यात्मिक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। आयोजन में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि महाराज ने कहा कि आज भी हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। पश्चात्य संस्कृति जीवन में शामिल हो रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो संबोधन प्रसारित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ धर्म के स्तंभ हैं।

ओडीओपी-सीएफसी परियोजनाओं को जनभागीदारी से जोड़ने पर योगी सरकार का जोर

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों, हस्तशिल्प, बुनकरी और सूक्ष्म उद्यमों को नई मजबूती देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है. सरकार की मंशा है कि ओडीओपी योजना के तहत स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) केवल सीमित लोगों तक न रहकर अधिक से अधिक कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं से जोड़ें.

इसी उद्देश्य से मंगलवार को प्रदेश में संचालित 16 सीएफसी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सीएफसी में सीमित लाभार्थियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि योजनाओं का लाभ केवल कुछ सदस्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. इसी उद्देश्य से सीएफसी परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान और 10 प्रतिशत उद्यमियों का योगदान रखा गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन, परीक्षण, स्किल ट्रेनिंग और कॉमन टूल्स जैसी सुविधाएं सुलभ हो सकें.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसी को जनहित से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें. इसके लिए मोबाइल संदेश, पम्पलेट, उद्योग बंधु बैठकों और मीडिया माध्यमों का उपयोग करने को कहा गया. साथ ही सभी सीएफसी में ह्वसिटीजन चार्टरह्व प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को उपलब्ध सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके.

बैठक में अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, वाराणसी, खुर्जा, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या और गाजियाबाद सहित विभिन्न जिलों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई. अंबेडकर नगर बुनकर सीएफसी में लगभग 4 करोड़ रुपये की सहायता से स्थापित परियोजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक बुनकर आधुनिक सुविधाओं से जुड़ सकें. वहीं बनारस के सिल्क उत्पाद सीएफसी में लगभग 9 करोड़ रुपये की सहायता से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक स्तर पर कारीगरों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई.

बैठक में बुनकरों और कारीगरों ने बिजली, धागे की लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा और तकनीकी उन्नयन से जुड़े मुद्दे भी रखे. समीक्षा के दौरान बताया गया कि योगी सरकार ने बुनकरों को राहत देने के लिए वर्षों तक फ्लैट रेट विद्युत योजना लागू रखी, जिसके तहत 2006 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 44 करोड़ रुपये का विद्युत व्यय सरकार द्वारा वहन किया गया. सरकार की प्राथमिकता है कि पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से जुड़े लोग आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें.

गाजियाबाद के इंजीनियरिंग एवं टूल रूम आधारित सीएफसी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वहां सीएनसी मशीन, 3डी प्रिंटिंग, मटेरियल टेस्टिंग और स्किल ट्रेनिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. अब तक 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और रक्षा क्षेत्र के लिए कंपोनेंट निर्माण की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है.

मुरादाबाद के फिजिकल वेपर डिपोजिशन (पीवीडी) प्लांट को पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उदाहरण बताते हुए उसकी कार्यक्षमता को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. वहीं संभल के बटन उद्योग सीएफसी में 70 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग को सकारात्मक संकेत बताते हुए कच्चे माल और बिजली उपलब्धता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.

खुर्जा ब्लैक पॉटरी सीएफसी को बैठक में सफलता की मिसाल बताया गया. इस परियोजना से 1253 से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं और कारोबार 15-20 लाख रुपये से बढ़कर 90-95 लाख रुपये तक पहुंचा है. इसे पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार से जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया. कारीगरों द्वारा मिट्टी भंडारण के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग भी बैठक में रखी गई.

सहारनपुर वुड क्राफ्ट, आगरा लेदर क्लस्टर, बरेली और मेरठ के गुड़ प्रसंस्करण सीएफसी की भी समीक्षा की गई. मेरठ परियोजना में 1800 किसानों को जोड़कर मूल्य संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उद्योग बंधु बैठकों का आयोजन सीएफसी परिसरों में किया जाए और बड़ी उद्योग इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर छोटे उद्यमों को बड़े बाजार और सप्लाई चेन से जोड़ा जाए.

भारत में संतुलित और आत्मनिर्भर उर्वरक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में इफको की भूमिका

(जीएनएस)।

भारत का कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। यह करोड़ों किसानों की आजीविका का आधार है और 140 करोड़ से अधिक लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे-जैसे देश कृषि के आधुनिकीकरण और ग्रामीण समृद्धि को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उर्वरक उद्योग इन लक्ष्यों को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इस परिवर्तन का नेतृत्व करने वाली संस्थाओं में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने भारतीय कृषि में स्थिरता, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले सबसे प्रभावशाली संगठनों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

किसान-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थापित इफको आज दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में शामिल है। दशकों से यह संगठन कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ जिम्मेदार और संतुलित खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इफको का योगदान केवल उर्वरक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसानों को सशक्त बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारत की दीर्घकालिक कृषि क्षमता को सुदृढ़ करने का एक व्यापक अभियान है।

भारत की उर्वरक व्यवस्था फसल उत्पादकता बनाए रखने और स्थिर खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, जिनमें वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, आयात पर निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न पर्यावरणीय चिंताएँ शामिल हैं।

इफको ने बड़े पैमाने की विनिर्माण क्षमता, किसान संपर्क कार्यक्रमों और नवाचार-आधारित कृषि समाधानों में निवेश के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण भारत तक फैले अपने विशाल सहकारी नेटवर्क के जरिए संगठन ने लाखों किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद, तकनीकी मार्गदर्शन और आधुनिक कृषि ज्ञान उपलब्ध कराया है।

इफको की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहकारी संरचना रही है, जिसमें किसान संगठन की विकास प्रक्रिया के केंद्र में रहते हैं। किसान-प्रथम दृष्टिकोण ने ग्रामीण समुदायों में विश्वास को मजबूत किया है और कृषि विकास में पहुँच, वहनीयता तथा समावेशिता सुनिश्चित की है।

परिवर्तन को दिशा देता नेतृत्व

दिलीप संघानी के नेतृत्व में इफको ने स्थिरता, नवाचार और किसान सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत किया है। अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि भारत के लिए एक मजबूत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु तकनीकी प्रगति और सहकारी मूल्यों का समन्वय आवश्यक है।

उनकी सोच आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास और टिकाऊ कृषि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उनके मार्गदर्शन में इफको ने नई पीढ़ी की उर्वरक तकनीकों पर कार्य तेज किया है, किसान-केंद्रित पहलों का विस्तार किया है और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को देशभर में बढ़ावा दिया है।

दिलीप संघानी ने इस आवश्यकता पर भी बल दिया है कि भारतीय कृषि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने, लेकिन उसकी जड़ें किसानों के कल्याण से जुड़ी रहें। उनके नेतृत्व ने इफको को केवल एक उर्वरक निमार्ता ही नहीं, बल्कि भारत की कृषि परिवर्तन यात्रा का एक रणनीतिक साझेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नैनो उर्वरकों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा

हाल के वर्षों में इफको की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का विकास और परिचय है। ये नवाचारी उत्पाद उर्वरकों के उत्पादन, वितरण और उपयोग के तरीकों में एक बड़ा बदलाव दर्शाते हैं।

नैनो उर्वरकों को पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाने और पारंपरिक उर्वरकों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। कम मात्रा में उपयोग और लक्षित पोषक आपूर्ति की क्षमता के कारण ये उत्पाद मिट्टी की क्षति कम करने, जल प्रदूषण घटाने तथा परिवहन और भंडारण लागत कम करने में सहायक हो सकते हैं।

नैनो उर्वरकों को अपनाना भारत के व्यापक स्थिरता लक्ष्यों और पर्यावरण-अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करने की सोच के अनुरूप है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, संसाधन संरक्षण और खाद्य सुरक्षा वैश्विक प्राथमिकताएँ बन चुकी हैं, इस प्रकार के नवाचार भारतीय कृषि के भविष्य में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। अनुसंधान और विकास में इफको का निवेश यह दर्शाता है कि भारतीय संस्थाएँ किसानों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नवाचार में वैश्विक नेतृत्व कर सकती हैं।

आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्थन

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उर्वरक क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से आयातित कच्चे माल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर रहा है, उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जहाँ आत्मनिर्भरता दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता ला सकती है।

घरेलू उत्पादन अवसंरचना, अनुसंधान क्षमता और उन्नत उर्वरक तकनीकों में इफको का निवेश इस राष्ट्रीय उद्देश्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने और नवाचारी उर्वरक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके संगठन भारत को अधिक मजबूत और लचीली कृषि अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। साथ ही, इफको के अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों ने ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी प्रगति और भारतीय कृषि की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है।

उर्वरकों से आगे बढ़ती स्थिरता

आधुनिक कृषि में स्थिरता केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और जिम्मेदार कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना भी शामिल है।

इफको ने ऊर्जा-कुशल विनिर्माण प्रणालियों, पर्यावरण संरक्षण पहलों और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने वाले किसान जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अपने संचालन को इन व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप ढाला है।

संगठन ने ग्रामीण भारत में सूचना के अंतर को कम करने के लिए डिजिटल पहलों और किसान शिक्षा कार्यक्रमों में भी निवेश किया है। तकनीक और व्यापक संपर्क नेटवर्क का उपयोग करके इफको किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल पोषण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जुड़े बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बना रहा है।

ऐसी पहलें एक ऐसे दीर्घकालिक कृषि ढाँचे के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो उत्पादकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखे।

आगे की राह

जैसे-जैसे भारत अपने कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण कर रहा है, इफको जैसे संगठनों की भूमिका खेती, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के भविष्य को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

नवाचार, स्थिरता और सहकारी विकास का समन्वय वर्तमान और भविष्य की कृषि चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। कुशल पोषक प्रबंधन, पर्यावरण-अनुकूल खेती और डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण समुदायों की दिशा में बढ़ता बदलाव भारत की कृषि विकास यात्रा के अगले चरण को परिभाषित करेगा।

अध्यक्ष दिलीप संघानी के नेतृत्व में इफको भारत के कृषि परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। तकनीकी नवाचार को सहकारी मूल्यों और किसान-केंद्रित विकास के साथ जोड़ते हुए संगठन भविष्य के लिए एक मजबूत, हरित और आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

तेजी से जटिल होती वैश्विक कृषि व्यवस्था में टिकाऊ और आत्मनिर्भर समाधानों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

दिल्ली में बनने जा रहा नया कारोबारिक सुपर जोन! एलजी का बड़ा ऐलान, द्वारका-रोहिणी-नरेला की बदलेगी तस्वीर

(जीएनएस)।

दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी के द्वारका, रोहिणी और नरेला इलाके आने वाले समय में बड़े कारोबारिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। इस दिशा में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने विकास प्राधिकरण अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।

योजना के तहत इन इलाकों में बड़े कारोबारी दफ्तर, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े केंद्र, डिजिटल ढांचा और वैश्विक कंपनियों के कार्यालय विकसित करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इससे दिल्ली में निवेश और रोजगार दोनों तेजी से बढ़ सकते हैं।

◆द्वारका को मिलेगा नया कारोबारिक दर्जा

द्वारका को राजधानी का नया आर्थिक केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक यहां पहले से बेहतर सड़क संपर्क, तेज रफ्तार मेट्रो नेटवर्क और बड़े रिहायशी क्षेत्रों का विकास हो रहा है।

इसके अलावा यशोभूमि और प्रस्तावित राजनयिक क्षेत्र भी द्वारका की अहमियत बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन अब इस इलाके को बड़े कारोबारी केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रहा है।

हाल ही में छऋटीएस संधु ने द्वारका उपनगर का दौरा भी किया था। इस दौरान कई अहम परियोजनाओं की समीक्षा की गई और विकास प्राधिकरण को नई संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए।

◆रोहिणी और नरेला पर भी बड़ा फोकस

सिर्फ द्वारका ही नहीं, बल्कि रोहिणी और नरेला को भी बड़े निवेश क्षेत्रों के रूप में तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन इलाकों में तेजी से नए आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। बेहतर सड़क परियोजनाओं और सार्वजनिक परिवहन की वजह से यहां लोगों की आवाजाही भी आसान हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब इन क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक और तकनीकी ढांचे की संभावनाएं तलाश रहा है।

◆बड़े भंडारण केंद्र और तकनीकी इकाइयों की तैयारी

अधिकारियों के मुताबिक नई सड़क परियोजनाओं और हवाई अड्डे से बेहतर संपर्क की वजह से इन इलाकों में बड़े भंडारण केंद्र, तकनीकी निर्माण इकाइयां और डिजिटल सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा नए शिक्षा केंद्र और रिहायशी परियोजनाएं भी इन क्षेत्रों को भविष्य के बड़े आर्थिक गलियारों में बदल सकती हैं। प्रशासन का मानना है कि अगर योजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो दिल्ली के बाहरी इलाके आने वाले वर्षों में कारोबार और निवेश के बड़े केंद्र बन सकते हैं।

◆सभी विभागों को साथ लेकर बनेगी योजना

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विभाग मिलकर जल्द विस्तृत योजना तैयार करें। सरकार का उद्देश्य सिर्फ भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा संतुलित विकास मॉडल तैयार करना है जिससे रोजगार, कारोबार और बुनियादी सुविधाएं एक साथ मजबूत हों।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली के पारंपरिक कारोबारी इलाकों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए आर्थिक क्षेत्रों का विकास जरूरी हो गया है। ऐसे में द्वारका, रोहिणी और नरेला आने वाले समय में राजधानी की नई पहचान बन सकते हैं।

अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका! ट्रंप का गुप्त प्लान लीक, टेंशन में दुनिया

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर 'सीक्रेट प्लान' अब दुनिया के सामने आ गया है। डेनमार्क और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में तीन नए सैन्य अड्डे बनाने को लेकर हाई-लेवल बातचीत चल रही है। ट्रंप ने पहले इसे खरीदने की इच्छा जताई थी और कब्जा करने तक की धमकी दी थी, जिससे नाटो देशों में तनाव बढ़ गया था।

अब अमेरिका सैन्य अड्डों के बहाने इस रणनीतिक द्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकना है।

सैन्य अड्डों के बहाने कब्जे की तैयारी?

अमेरिकी सरकार ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में तीन नए बेस बनाने का प्रस्ताव दे चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन अड्डों पर यह लिखा जा सकता है कि यह अमेरिका का संप्रभु इलाका है। यह एक तरह से बिना युद्ध किए ग्रीनलैंड के एक हिस्से पर सीधा नियंत्रण पाने जैसा है। ट्रंप का मानना है कि चीन और रूस को आर्कटिक क्षेत्र से दूर रखने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिकाना हक लेना ही होगा, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े।

रूस और चीन पर कड़ी नजर

ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से उत्तरी अटलांटिक महासागर, आइसलैंड और ब्रिटेन तक के समुद्री रास्तों पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका इन अड्डों का इस्तेमाल रूस और चीन की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए करना चाहता है। व्हाइट हाउस का मानना है कि अगर आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका मजबूत नहीं हुआ, तो भविष्य में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। इसलिए इन अड्डों को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तैनात होगा 'गोल्डन डोम' सिस्टम

अमेरिका ग्रीनलैंड में अपने आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 'गोल्डन डोम' को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसका मकसद रूस या चीन की तरफ से होने वाले किसी भी मिसाइल हमले को हवा में ही नष्ट करना है। इनमें से एक बेस 'नारसरसुआक' में बन सकता है, जहां पहले भी अमेरिकी सेना का बेस रह चुका है। अमेरिका इस पूरे द्वीप को एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि उसकी मुख्य भूमि पूरी तरह सुरक्षित रहे।

डेनमार्क के साथ जारी है गुप्त वार्ता

भले ही ट्रंप की धमकियों से डेनमार्क पहले नाराज था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ रही है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि बातचीत सही दिशा में है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

'सनातन को खत्म कर देना चाहिए,' स्टालिन ने विधानसभा में उगला जहर, सीएम विजय ने हाथ जोड़ किया समर्थन?

(जीएनएस)।

तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ऊटङ नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा के भीतर बोलते हुए कहा कि "लोगों को बांटने वाले सनातन को खत्म किया जाना चाहिए।" उनके इस बयान के बाद सदन से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई है। इखढ ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया है, जबकि इस बयान से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

राजनीतिक विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री विजय का भी जिक्र किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो को अलग-अलग दावों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट की पुरानी टिप्पणी भी फिर चर्चा में आ गई है, जिसमें अदालत ने उदयनिधि के बयान को "हेट स्पीच" बताया था।

तमिलनाडु विधानसभा के सत्र के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि "सनातनम लोगों को अलग करता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए।" उनके बयान में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भी विवाद हो रहा है।

उन्होंने तमिल शब्द "ओझिप्पु" का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब "समाप्त करना" या "खत्म करना" होता है। राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सनातन धर्म को मिटाने की बात है। उदयनिधि इससे पहले भी सनातन

धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले बयान के बाद देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और कई जगह उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हुई थीं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उदयनिधि-विजय का वीडियो

विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ा एक वीडियो अब एक्स ( ) यानी पहले ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ कई यूजर्स अलग-अलग दावे कर रहे हैं।

एक वायरल पोस्ट में लिखा गया, "आज तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि 'सनातन को खत्म कर देना चाहिए', जबकि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। क्या यह सहमति का संकेत था? जरा सोचिए, अगर किसी हिंदू नेता ने मुसलमानों या ईसाइयों के बारे में ऐसा कुछ कहा होता तो क्या होता? विडंबना उन हिंदुओं के साथ है जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं।"

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने इसे धार्मिक मुद्दा बताते हुए नाराजगी जताई, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। कई लोगों ने वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए सवाल उठाए कि आखिर विधानसभा में इस तरह की टिप्पणी क्यों की गई। सवाल ये भी है कि सीएम विजय ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? हालांकि, वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है।